PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 039
दि. 08.06.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

योगी सरकार लाएगी नई डेटा सेंटर नीति, एआई और ग्रीन डेटा सेंटर्स को मिलेगी प्राथमिकता

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश में 2 गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अभी से ठोस तैयारी करनी होगी।

रविवार को उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति–2021 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक आकर्षक, व्यावहारिक और समयानुकूल नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति में एआई आधारित डेटा सेंटर, ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन डेटा सेंटर, विश्वस्तरीय डिजिटल अवसंरचना, त्वरित अनुमोदन प्रणाली, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा बेहतर कनेक्टिविटी जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश देश में डेटा सेंटर निवेश का सबसे पसंदीदा केंद्र बन सके।

प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2026 तक देश की कुल डेटा सेंटर क्षमता में उत्तर प्रदेश

की हिस्सेदारी लगभग 8 से 9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर नीति–2021 के तहत 900 मेगावाट क्षमता विकसित करने तथा 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष अब तक 21,342.90 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं और निवेशकों को लेटर ऑफ कंफर्ट भी जारी किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में छह डेटा सेंटर पार्क और दो डेटा सेंटर इकाइयां संचालित हैं, जबकि 644 मेगावाट की प्रतिबद्ध क्षमता पर कार्य प्रगति पर है।

नई डेटा सेंटर नीति के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि, पूंजी और ऋण संबंधी अनुदानों के साथ–साथ स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क तथा ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग शुल्क में दी जाने वाली रियायतों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने एआई आधारित उच्च क्षमता वाली कम्प्यूटिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्नत एआई कम्प्यूट संसाधन स्थापित करने वाले डेटा सेंटर पार्कों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे प्रदेश में एआई आधारित डिजिटल अवसंरचना के विकास को बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने डेटा सेंटर क्षेत्र में हरित और टिकाऊ विकास को विशेष महत्व देते हुए कहा कि उच्च स्तर का ग्रीन डेटा सेंटर प्रमाणन प्राप्त करने वाली इकाइयों और पार्कों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बैठक में अधिकारियों ने प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि हीरानंदानी समूह, एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स, अडानी समूह, एसटी टेलीमीडिया, एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, वेब वर्क्स तथा सिफी सहित कई प्रमुख कंपनियों की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बड़े स्तर पर डिजिटल अवसंरचना का विकास हो रहा है।

बैठक में संभावित निवेश प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने प्रदेश में कुल 5,410 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर विकसित करने में रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं में लगभग 4.90 लाख करोड़ रुपये के संभावित निवेश का अनुमान है। प्रस्तावित निवेशों में एएम ग्रीन, ट्राइफैक्टा कॉनेक्स, एस्सार, ग्रू एनर्जी, गोल्डन स्टेट कैपिटल, मैपलेट्री, सीटीआरएल–एस, एनएक्स्ट्रा सहित अन्य प्रमुख निवेशकों की परियोजनाएं शामिल हैं। इनके लिए नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और सीतापुर समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेटा सेंटर विकास को केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रदेश के अन्य उपयुक्त शहरों और क्षेत्रों में भी डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित किए जाएं, ताकि डिजिटल निवेश और रोजगार के अवसरों का लाभ प्रदेश के

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, परीक्षार्थियों को मिल जाएगी राहत

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के बस से सफर करने पर बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को बस किराए में 50 फीसदी की छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। सरकार की ओर से इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी कर दिए हैं। परिवहन विभाग की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश को लागू कराया जाएगा। इससे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिल जाएगी।

यूपी सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है। यूपी रोडवेज की बसों में इस प्रकार की सुविधा के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।

तीन दिन होनी है परीक्षा

यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा तीन दिन 8 से 10 जून तक होनी है। परीक्षा दो पालियों में होगी। इसके लिए राज्य भर में 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 28.86 लाख महिला और पुरुष परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों पर तीन स्तरीय जांच होगी। किसी प्रकार की नकल जैसी स्थिति से बचने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं।

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की गेट पर बायोमेट्रिक जांच और ई–केवाईसी होगी। इसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश मिलेगा। सीएम योगी ने पहले ही भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने देने के सख्त निर्देश दिए हैं।

दार्जलिंग में तीस्ता नदी में समाई कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर से बड़ी ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तीस्ता नदी में कार गिर

गई जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा सेवोके और कर्सियांग के पास शुक्रवार की शाम को हुआ। जिसमें पूरी कार नदी में समा गई थी। NDRF सिलीगुड़ी की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और कार को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।

NDRF के डिप्टी कमांडेंट संजय रंजन ने जानकारी दी। प्रशासन ने मौके पर तुरंत राहत टीम भेजी थी।

आयुष विभाग के विवादित तबादलों पर सीएम योगी का संज्ञान, रद हो सकते हैं अनियमित ट्रांसफर

राज्य मंत्री दयाशंकर का कहना है कि अधिकारियों के बीच संवाद की कमी से शिथिलता संभव है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) विभाग के तबादलों का विवाद तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबादलों में अनियमितता का संज्ञान लिया है। शनिवार को तबादलों से जुड़ी जानकारी जुटायी गयी।

पूछताछ में सामने आया है कि समूह ख के 15 कार्मिकों का तबादला कई बार संशोधित किया गया है। ऐसे सभी दागदार छवि वाले कार्मिकों के तबादले रद हो सकते हैं।

अनुमोदन के बगैर किये गये तबादलों को रद करने के लिए मुख्य सचिव को महानिदेशक (डीजी)

चैत्रा.वी द्वारा पत्र लिखने के बाद आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र दयालु रविवार को पूर्वांचल का दौरा छोड़कर लखनऊ पहुंचे।

आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के निदेशकों को सरकारी आवास पर बुलाकर तबादला प्रकरण पर चर्चा की। बैठक में डीजी नहीं पहुंची। अब राज्यमंत्री ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी है।

राज्य मंत्री दयाशंकर का कहना है कि अधिकारियों के बीच संवाद की कमी से शिथिलता संभव है। तबादलों में डीजी की अनदेखी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पत्रावलियों का अवलोकन करने पर ही स्थिति साफ होगी।

युद्ध के चलते लड़खड़ा गई भारत की गाड़ी...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक नेतृत्व ने थाम ली स्टीयरिंग!

मिडिल ईस्ट युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट संकट के चलते खाड़ी देशों से भारत समेत एशियाई देशों को पेट्रोल–डीजल और एलपीजी की सप्लाई लड़खड़ा गई। हालांकि, पीएम मोदी बार–बार देशवासियों को तेल–गैस का भरोसा दे रहे हैं, जो भारत की मजबूत ताकत को दशार्ता है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः अमेरिका–ईरान युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पिछले महीने कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग में इस साल कम वृद्धि होने की आशंका है। ट्रक परिवहन क्षेत्र में तनाव के शुरूआती संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं, सरकारी खुदरा विक्रेताओं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने चुनावों के कारण पहले कीमतों में बढ़ोतरी न करने के बाद मई के मध्य से अब तक चार चरणों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतें अब 7.8% और डीजल की कीमतें 8.6% बढ़ गई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि युद्ध ने भले ही संकट में डाला हो, मगर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक नेतृत्व ने इस संकट से उबार लिया है।

सोशल मीडिया एक्स पर न्यूज एजेंसी आईएएनएस के हवाले से घरेलू एलपीजी की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी पर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'भू–राजनीतिक अस्थिरता और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे संघर्षों के कारण दुनिया भर के कई देशों को डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की आपूर्ति से संबंधित कमी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि एलपीजी गैस की कोई कमी न हो। यह हमारे देश की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रणनीतिक नेतृत्व को दशार्ता है। उनकी प्रभावी योजना और नीति निर्माण ने देश को एक बड़े संकट से बचाने में मदद की है...'

कीमतों में और हो सकती है बढ़ोतरी

न्यूज एजेंसी रायटर्स पर छपी एक खबर में विश्लेषकों का कहना है कि कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, जिससे मांग और कम होने की संभावना है, क्योंकि खुदरा विक्रेता अभी भी ईंधन को बाजार दर से कम दामों पर बेच रहे हैं और उन्हें प्रतिदिन कुल मिलाकर 5.5 अरब रुपये (57 मिलियन डॉलर) का नुकसान हो रहा है।

चीन नहीं भारत के चलते पड़ेगा दुनिया पर असर

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक और उपभोक्ता भारत में ईंधन की बिक्री में धीमी वृद्धि से वैश्विक मांग के दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि चीन में परिवहन ईंधन की खपत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एफजीई नेक्सेंटईसीए के विश्लेषक डायलन सिम ने कहा–'हमारा अनुमान है कि विवेकाधीन ड्राइविंग में कमी के कारण 2026 में भारत में गैसोलीन की मांग में वृद्धि दर घटकर लगभग 3.5–3.7% रह जाएगी।' यह पहले के 4% वृद्धि के अनुमान से कहीं अधिक है। कंसल्टेंसी ने डीजल की मांग में वृद्धि के अपने पूवार्नुमान को भी 2.5% से घटाकर 2% कर दिया है। ट्रक चालकों को वापसी की माल ढुलाई नहीं मिल रही है। उत्पादन धीमा होने के कारण 3–5 दिनों की देरी हो रही है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है क्योंकि प्रति माह उनकी आने–जाने की यात्राएं कम हो गई हैं।

मूडीज की भारतीय रेटिंग का पूवार्नुमान घटा

मूडीज की भारतीय रेटिंग शाखा कउफ्क्ष ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पेट्रोल की मांग में वृद्धि के अपने पूवार्नुमान को संशोधित करते हुए इसे 3% से 4% तक कम कर दिया है, जबकि युद्ध से पहले यह 5% से 6% था।

भारत की मेजर अभिलाषा बराक को मिला यूएन में अवॉर्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को हरियाणा की मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिलने पर बधाई दी।

पीएम ने कहा कि यह सम्मान उनकी बेहतरीन सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति–स्थापना प्रयासों में भारत के लंबे समय से चले आ रहे योगदान की पहचान है।

बराक अभी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम कर रही हैं। उन्हें यह अवॉर्ड पश्चिम एशियाई देश में अपनी तैनाती के दौरान महिलाओं और लड़कियों के साथ जुड़ने और उनके लिए काम करने की कोशिशों के लिए दिया गया है। वह भारतीय सेना की पहली महिला काम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं।

पीएम मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को दी बधाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल पाइंट के तौर पर काम कर रही हैं।

पीएम ने कहा, 'यह सम्मान उनकी बेहतरीन सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति–स्थापना प्रयासों में भारत के लंबे समय से चले आ रहे योगदान की पहचान है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवा भारतीयों, खासकर हमारी बेटियों के लिए भी प्रेरणा है, जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं।'

संयुक्त राष्ट्र शांति–स्थापना के अनुसार, हर साल सभी शांति अभियानों के फोर्स कमांडरों और मिशन प्रमुखों द्वारा नामिनेट किए गए उम्मीदवारों में से अवार्ड पाने वाले को चुना जाता है।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर फिदा हुए ट्रंप! मोजतबा खामेनेई को लेकर दिया ऐसा बयान कि हिल गई पूरी दुनिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि मोजतबा अपने पिता से "ज्यादा समझदार" हैं और न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रतिबंधों और यूरेनियम स्टॉकपाइल को लेकर बातचीत जारी है। ट्रंप के इस बयान ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन नई ईरानी लीडरशिप के साथ बातचीत की संभावना को खुला रखना चाहता है।

लखनऊ की बदलती तस्वीर का राजनाथ ने दिया ब्योरा, बोले- विकास, सुरक्षा और नवाचार का संगम बना शहर

केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले एक दशक में लखनऊ ने आधारभूत ढांचे, रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कभी ट्रैफिक जाम से जूझने वाला लखनऊ आज रिंग रोड, एक्सप्रेस–वे, मेट्रो और रक्षा परियोजनाओं के दम पर नई पहचान गढ़ रहा है।

(जीएनएस)।

लखनऊ, केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले एक दशक में लखनऊ ने आधारभूत ढांचे, रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कभी ट्रैफिक जाम से जूझने वाला लखनऊ आज रिंग रोड, एक्सप्रेस–वे, मेट्रो और रक्षा परियोजनाओं के दम पर नई पहचान गढ़ रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और युवाओं की नवाचार क्षमता को भी भारत की नई ताकत बताया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में सांसद बनने के बाद शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम थी। इसे दूर करने के लिए रिंग रोड परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका लाभ आज लाखों शहरवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के निर्माण से यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आया है और शहर की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ अब रक्षा उत्पादन और अनुसंधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना समेत कई रक्षा इकाइयों को बढ़ावा दिया गया है। डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के विस्तार से युवाओं के लिए शोध, तकनीक और नवाचार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिकांश रक्षा उपकरण अब देश में ही तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख मजबूत हुई है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेड गिरने के मामले में लापरवाही आई सामने, कई मंडलों में लोहे की गुणवत्ता की होगी जांच

(जीएनएस)।

लखनऊ। लागत को कम करने के लिए भारी भरकम लोहे (स्टील आयरन) की जगह कास्टिंग आयन (पाइप आधारित लोहे) के शेड का इस्तेमाल तेजी से रेलवे में बढ़ा है। कास्टिंग आयरन का उपयोग भारी भरकम लोहे का वजन को संभालने के लिए हो रहा है। यह यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

लखनऊ (चारबाग) स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच का शेड गिरने के मामले की जांच कर रही कमेटी ने स्ट्रक्चरल आडिट के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को अपने यहां स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड की गुणवत्ता को जांचने के आदेश दिए हैं।

विभिन्न रेल मंडलों में वजनी लोहे के स्ट्रक्चरल के स्थान पर पाइप आधारित शेड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर निर्धारित मानकों से कम मोटाई (अंडरगेज) पाइप लगाए जाने

की शिकायतें भी मिली हैं। लखनऊ में भी प्लेटफॉर्म शेड के निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों में लागत कम करने के लिए मूल डिजाइन और सामग्री में बदलाव किए गए।

लखनऊ स्टेशन की घटना का संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड के निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपों की वास्तविक मोटाई, डिजाइन अनुमोदन की प्रक्रिया और कार्यदायी एजेंसियों की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री के नमूनों का परीक्षण भी कराया जाएगा।

बीती 29 मई को सुबह आठ बजे लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच का 115 टन वजनी शेड गिर गया था। इस हादसे में एक टीटीई और दो रेल यात्री घायल हो गए थे।

इस मामले में सहायक रेलवे अभियंता, वर्क्स इंजीनियर, आरएलडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया था। जबकि निर्माण कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया गया।

घटना की जांच के लिए जोनल रेलवे स्तर के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनायी गई है। इस समिति ने पिछले दिनों लखनऊ आकर घटनास्थल की जांच की थी। घटना से जुड़े 17 अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किये गए थे।

लखनऊ से गोरखपुर के बीच 10 जून तक चलेंगी चार परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)।

लखनऊ। पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच चार परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेशभर में करीब 28 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए रविवार से दस जून तक चार परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 05031 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल गोरखपुर से शाम सात बजे चलकर खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, करनैलगंज,

बाराबंकी होते हुए रात 12:20 बजे बादशाहनगर व रात 12:55 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05032 लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन लखनऊ जं. से शाम सवा छह बजके चलकर बादशाहनगर से शाम 6:48 बजे होते हुए उपरोक्त स्टेशनों के रास्ते गोरखपुर रात 11:55 बजे पहुंचेगी। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 05005 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गोरखपुर से दोपहर 1:30 बजे चलकर खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, करनैलगंज, बाराबंकी होते हुए बादशाहनगर शाम 5:42 बजे व लखनऊ जंक्शन शाम सवा छह बजे पहुंचेगी। वापसी में 05006 लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष लखनऊ जंक्शन से दोपहर डेढ़ बजे चलकर बादशाहनगर दोपहर 1:52 बजे होते हुए उपरोक्त स्टेशनों के रास्ते गुजरते हुए गोरखपुर शाम 6:50 बजे पहुंचेगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेनों में जनरल के दस कोच लगाए जाएंगे।

नए कलेवर में नजर आएगा लखनऊ का लोक कला संग्रहालय

प्रदेश की समृद्ध लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए संग्रहालय में नई गैलरियों, बच्चों के एक्टिविटी जोन, वर्कशॉप स्पेस, लैंडस्केप अपग्रेडेशन और लोक कला इंस्टॉलेशन के समेकित विकास की योजना तैयार की गई है।

(जीएनएस)।

लखनऊ , राजधानी के चिड़ियाघर स्थित लोक कला संग्रहालय अब एक नए और आकर्षक स्वरूप में नजर आने वाला है। प्रदेश की समृद्ध लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए संग्रहालय में नई गैलरियों, बच्चों के एक्टिविटी जोन, वर्कशॉप स्पेस, लैंडस्केप अपग्रेडेशन और लोक कला इंस्टॉलेशन के समेकित विकास की योजना तैयार की गई है। इसके विकास के लिए लगभग 1.98 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

इस परियोजना के तहत संग्रहालय परिसर को अधिक जीवंत, संवादात्मक और अनुभवात्मक बनाया जाएगा। प्रवेश द्वार की दीवारों का आकर्षक अपग्रेडेशन किया जाएगा, वहीं पारंपरिक भारतीय मान्यताओं को दर्शाने वाला नींबू-मिर्ची इंस्टॉलेशन भी विकसित किया जाएगा। संग्रहालय में लोक कला का परिचय, रामायण के प्रभाव तथा प्रागैतिहासिक काल से लोक कला के विकास को कला, प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक प्रस्तुतीकरण तकनीकों के माध्यम से

दशार्या जाएगा। परियोजना के अंतर्गत एक विशेष डॉल डिस्प्ले गैलरी, आधुनिक रिसेप्शन और प्राथमिक चिकित्सा कक्ष भी विकसित किया जाएगा। संग्रहालय की प्रत्येक मंजिल पर अलग-अलग थीम आधारित इमर्सिव रास्ते तैयार किए जाएंगे। जिनमें रस्सियों, दीवार चित्रों, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तकनीक, मिट्टी के सिमुलेशन, फूस की छतों, पारंपरिक कुओं और झोपड़ियों जैसे रचनात्मक इंस्टॉलेशन शामिल होंगे।

लोक कला और शिल्प को व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए संग्रहालय में विशेष कला इंस्टॉलेशन और क्रिएटिव पार्टिशन भी बनाए जाएंगे। मिट्टी के बर्तन बनाने के स्टूडियो और टिकट आधारित ट्रेनिंग क्लासेज के साथ क्ले गैलरी विकसित की जाएगी। जहां आगंतुक स्वयं भी इस कला को सीख सकेंगे। इसके अलावा पारंपरिक घरेलू जीवन को प्रदर्शित करने के लिए धातु और लकड़ी से जुड़ी कलाकृतियों तथा उपयोगी वस्तुओं के साथ मेटल एवं वुड गैलरी तैयार की जाएगी। संग्रहालय में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तकलाओं को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। चिकनकारी, जरी और जरदोजी जैसी पारंपरिक कलाओं को अलग-अलग इंस्टॉलेशन शैली में प्रदर्शित करने के लिए फैब्रिक गैलरी विकसित की जाएगी। वहीं, कार्पेट निर्माण की परंपरा को दशार्ने के लिए कार्पेट गैलरी और कार्पेट टफ्टिंग एक्टिविटी एरिया बनाया जाएगा। जहां आगंतुक इस कला की बारीकियों को नजदीक से समझ सकेंगे। साथ ही एक कॉमन ब्रेक-आउट एरिया और ड्राई पैंट्री कैफे लाउंज भी विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत मौजूदा गैलरियों की स्टोरीलाइन को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा और अतिरिक्त डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे। ताकि संग्रहालय की प्रस्तुति और अधिक प्रभावशाली बन सके। लोक कला संग्रहालय परिसर में प्रस्तावित यह समेकित विकास कार्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देने के साथ-साथ लखनऊ को सांस्कृतिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

'एक व्यक्ति अहंकार में चूर होकर शंकराचार्य का अपमान करता है', सीएम योगी पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हमला

(जीएनएस)।

आगरा में गविष्टि यात्रा के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर निशाना साधते हुए गाय को माता घोषित करने की मांग उठाई. उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है और सरकारें अपने वादे निभाने में विफल रही हैं. वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य का सम्मान करने की बात कही, लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमला बोला.

आगरा पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला. गो संरक्षण एवं जनजागरण के उद्देश्य से निकाली जा रही गविष्टि यात्रा के तहत रविवार को राजपुर चुंगी स्थित परशुराम मंदिर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई और लोगों से ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने का आह्वान किया जो गाय को माता का दर्जा देने के पक्ष में हों.

अऊश्एफ्ळकरएटएठळ

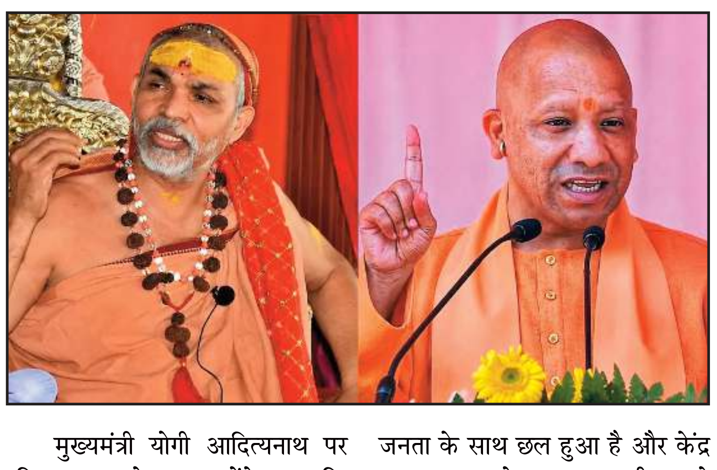

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अहंकार में चूर होकर उनका अपमान कर रहा है. उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का अपमान मुगलों और अंग्रेजों ने भी नहीं किया था. यदि कोई व्यक्ति गलत है तो उसे गलत कहना ही पड़ेगा.

शंकराचार्य ने कहा कि देश में गाय को माता का दर्जा देने का वादा वर्षों से किया जाता रहा है, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि पिछले 78 वर्षों में जनता के साथ छल हुआ है और केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है. उन्होंने कहा कि गोमाता की पीड़ा को न समझना जनता के साथ धोखा है.

उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है, बल्कि गाय को माता घोषित कराने के लिए है. यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय को माता घोषित करते हैं तो वे उनकी भी प्रशंसा करेंगे. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के भीतर दो विचारधाराएं हैं. एक भाजपा गाय और संतों का सम्मान करती है, जबकि दूसरी गाय को माता कहने और संतों का सम्मान करने को तैयार नहीं है.

राजनीतिक दलों की परीक्षा की बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सभी नेताओं और दलों को औपचारिक रूप से गाय को माता स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने बताया कि अब तक इस कसौटी पर केवल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खरे उतरे हैं.

इस बीच आगरा पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं. हालांकि सैफई में शंकराचार्य के सम्मान को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. मौर्य ने इसे सैफई परिवार का ढोंग बताते हुए कहा कि राम और शिव भक्तों पर गोली चलवाना उनका वास्तविक चरित्र रहा है तथा समाजवादी पार्टी वर्ष 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाली.

पंचायती राज मंत्रालय 09 जून 2026 को गांधीनगर, गुजरात में एक जनसंपर्क कार्यशाला एवं आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का आयोजन करेगा

कार्यशाला का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे गुजरात के पात्र ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक पंचायत शामिल होंगे

(जीएनएस)।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 09 जून 2026 को गांधीनगर, गुजरात में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर एक आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री विवेक भारद्वाज, पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मुक्ता शेखर, गुजरात सरकार के पंचायत, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री धनंजय द्विवेदी, गुजरात सरकार के अतिरिक्त विकास आयुक्त डॉ. गौरव दहिया, गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

इस कार्यशाला का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। इसमें गांधीनगर के आसपास स्थित पात्र पंचायतें व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे जबकि इस दायरे से बाहर स्थित पंचायतें अपने-अपने कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव शामिल होंगी। मंत्रालय का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से पूरे गुजरात में ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक पंचायत स्तर के नेताओं से सीधे जुड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना, उद्देश्य एवं परिचालन रूपरेखा से अवगत कराना है।

कार्यशाला के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर अपने दृष्टिकोण पर प्रकाश डालेंगे साथ ही इसमें राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों, तकनीकी रूपरेखा एवं अपेक्षित परिणामों पर विस्तृत प्रस्तुति, आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल का लाइव प्रदर्शन एवं एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र शामिल है। नाबार्ड और हुडको के प्रतिनिधि भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे तथा कार्यक्रम के प्रति अपने संस्थानों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसका संचालन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, एक पारदर्शी राष्ट्रीय चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों को आमंत्रित किया जाता है कि वे ऐसी राजस्व-निर्माण परियोजनाओं एवं पहलों के लिए अपने विचार प्रस्तुत करें जो अनुपयोगी संपत्तियों एवं अप्रयुक्त स्थानीय अवसरों का उत्पादक उपयोग करें। चयनित विचारों को योजना अनुरूप, बैंक योग्य परियोजनाओं में विकसित करने के लिए मंत्रालय से समर्पित तकनीकी सहायता प्राप्त होगी, जिसमें धन समर्थन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान, बैंक वित्त और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय से प्राप्त होगा। सामुदायिक स्वामित्व ग्राम सभा की प्रत्येक योजना चरण में अनिवार्य सहभागिता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

सभी ग्राम पंचायतें जिनका न्यूनतम स्वयं स्रोत राजस्व (ओएसआर) 50 लाख रुपये है और सभी ब्लॉक पंचायतें जिनका न्यूनतम ओएसआर एक करोड़ रुपये है, और दोनों की अवधि में कम से कम तीन साल शेष हैं, इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पंचायत राज मंत्रालय ने ग्रामीण परियोजना विकास में संस्थागत विशेषज्ञता प्रदान करने और योग्य पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड और हुडको के साथ साझेदारी की है।

राष्ट्रीय ग्राम शासन अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सक्षम पंचायतों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है, जो इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करें कि वित्तीय स्वतंत्रता और स्वशासन एक दूसरे के पूरक है। मंत्रालय की सोच है कि एक आत्मनिर्भर पंचायत आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत नींव है। गांधीनगर कार्यशाला गुजरात राज्य में कार्यक्रम के विस्तार की शुरूआत का प्रतीक है।

मेरठ में अवैध मदरसों की जांच की मांग: विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए

(जीएनएस)।

मेरठ के जागृति विहार निवासी भाजपा नेता राहुल ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर जिले और आसपास के क्षेत्रों में संचालित कथित अवैध मदरसों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ मदरसों का संचालन बिना आवश्यक दस्तावेजों के किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में राहुल ठाकुर ने दावा किया है कि कुछ मदरसों को विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संस्थानों में बच्चों को भड़काने का काम किया जाता है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भाजपा नेता ने अपने पत्र में किठौर, भावनपुर और इचौली समेत कई क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ऐसे मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनके पास आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद इन संस्थानों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

राहुल ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कथित अवैध मदरसों की जांच खुफिया विभाग और संबंधित एजेंसियों से कराई जाए। उनका कहना है कि जांच के माध्यम से इन संस्थानों की गतिविधियों और फंडिंग के स्रोतों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

संभल में योगी आदित्यनाथ के जीवन पर प्रतियोगिता:विश्व हिंदू महासंघ ने 55वें जन्मोत्सव पर कराई परीक्षा

(जीएनएस)।

सम्भल के नरौली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 55वें जन्मोत्सव पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित इस परीक्षा में छात्र-छात्राओं ने योगी आदित्यनाथ के जीवन और व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दिए। यह आयोजन महासंघ द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा था।

यह प्रतियोगिता विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश कुमार शर्मा के निर्देशन और विद्यालय प्रबंधक राकेश शर्मा के व्यवस्थापन में संपन्न हुई। आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरणादायी व्यक्तित्वों से परिचित कराना और उनमें सामान्य ज्ञान तथा अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाना है।

इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, नरौली नगर महामंत्री मुकेश शर्मा, नगर मंत्री सुनील तिवारी, नगर मीडिया

प्रभारी अमन श्रीवास्तव और आचार्य ज्योति सहित कई पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया।

जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं और उन्हें समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे।

वहीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी समारोह में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी दास प्रजापति के हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र और पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विद्यालय परिवार और संगठन पदाधिकारियों ने संतोष व्यक्त किया।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे टूनार्मेंट में बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वास जताया कि टीम की यह सफलता देशभर की युवा खिलाड़ियों को आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि यह उपलब्धि भारत में महिला फुटबॉल की बढ़ती ताकत को दशार्ती है और देश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत आने वाले समय में और अधिक युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी दीं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को रिकॉर्ड छठी बार सैफ चैंपियनशिप

जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस सफलता से देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। श्री सिंह ने सभी खिलाड़ियों को निरंतर सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भी भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए इसे भारतीय फुटबॉल के लिए गर्व का क्षण बताया।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे टूनार्मेंट में बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वास जताया कि टीम की यह सफलता देशभर की युवा खिलाड़ियों को आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि यह उपलब्धि भारत में महिला फुटबॉल की बढ़ती ताकत को दशार्ती है और देश के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत आने वाले समय में और अधिक युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएँ भी दीं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को रिकॉर्ड छठी बार सैफ चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस सफलता से देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। श्री सिंह ने सभी खिलाड़ियों को निरंतर सफलता और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भी भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए इसे भारतीय फुटबॉल के लिए गर्व का क्षण बताया।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

कीमतों में वैश्विक बवाल के कारण वृद्धि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसीपीएम) के सदस्यों के साथ बैठक कर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान चर्चा का मुख्य विषय जीवन की सुगमता और कारोबारी सुगमता को और अधिक बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया।

दरअसल एकतरफ जहां वैश्विक स्थिरता के दौर में भी मार्च तिमाही में 7.8 व 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ी वहीं मुद्रास्फीति की जो दर 4 प्रतिशत से कम थी उसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है। उपभोक्ता वस्तुओं में महंगाई की मार तो बढ़ी है जिसका एकमात्र कारण पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और खाना पकाने की गैस की कीमतों में वैश्विक बवाल के कारण वृद्धि है।

सच तो यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लम्बा चलने की वजह से ही यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा था किन्तु अमेरिका और ईरान युद्ध ने तो सीधे ही अन्य देशों के साथसाथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। भारतीय अर्थशास्त्री पहले तो मानते थे कि भारत 40 देशों से कच्चा तेल लेता है इसलिए उसके ऊपर ईरान युद्ध से पड़ने वाला नहीं है। कदाचित भारतीय अर्थशास्त्रियों का यह आकलन सच भी साबित हो जाता किन्तु ईरान ने खाड़ी के अमेरिकी मित्र देशों पर हमले करके तथा होर्मूज स्ट्रेट से तेल लेकर जा रहे जहाजों को रोकने की वजह से सभी सम्बन्धित देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वास्तविकता तो यह है कि ईरान में राजनेताओं के मारे जाने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक आमी ने दिशाहीन कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ईरान के राजनेता सेना के इस तरह के व्यवहार का विरोध कर ही नहीं सके। ईरानी सेना ने स्वयं लक्ष्य निर्धारित किया और खुद ही पैसले लिए। यही कारण है कि जिस ईरान से भारत खुद ही तेल नहीं खरीदता था, वह ईरान भारतीय झंडा लगे जहाजों को रास्ता देने का निर्णय ले रहा था।

हैरानी की बात तो यह है कि भारत में उत्पादकता बढ़ने से वृद्धि दर बढ़ती जा रही है किन्तु वह ढांचा इस देश के पास नहीं है जो आर्थिक वृद्धि दर के बढ़ने पर उसका त्वरित लाभ आम उपभोक्ताओं एवं कारोबारियों को दे सके। आज की बैठक में सरकार की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक मुश्किलों को हल करने की कोशिश की गई है। एक अच्छी अर्थव्यवस्था का लक्षण है कि मुद्रास्फीति की दर जब तक आर्थिक वृद्धि दर से आधी नहीं रहेगी तब तक वित्तीय आर्थिक स्थिरता का दावा नहीं किया जा सकता। यही कारण है जब किसी देश में आर्थिक वृद्धि दर भी बढ़े और मुद्रास्फीति भी बढ़े तो ऐसी अर्थव्यवस्था के सामने कई असामान्य चुनौतियां आहट देती हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री के साथ संपन्न हुई आर्थिक सलाहकार के सदस्यों की बैठक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जैसे-जैसे बढ़ेगा आम उपभोक्ता और व्यवसायी दोनों को इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए आर्थिक सलाहकार परिषद का चिन्तन देश के सभी वगरे के जीवन को प्रभावित करने में सक्षम होगा।

लखनऊ के चिकनकारी कपड़े की पहुंच देश समेत दुबई, यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों तक

दिल्ली हाट में लखनऊ की असली चिकनकारी का स्टॉल लगा हुआ है. यहां लखनऊ के कारोबारी मोहम्मद अरमान ने 200 रुपये से 5 लाख तक की कुर्ती, सलवार सूट और साड़ियां रखीं हैं. बता दें कि लखनऊ का चिकनकारी कपड़ा देश समेत दुबई, यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों तक जाता है.

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः अगर आप भी शादी-ब्याह के मौसम में कुछ ऐसा पहनना चाहते हैं. जो भीड़ से अलग दिखे और आपके लुक में नवाबी नफासत का तड़का लगा दे तो यह खबर आपके लिए है. लखनऊ की मशहूर चिकनकारी अपनी बारीक कढ़ाई, खूबसूरत डिजाइनों और शाही अंदाज के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. अब इसी चिकनकारी की नजाकत दिल्ली तक पहुंच चुकी है, जहां एक ही छत के नीचे 400 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की साड़ियां, सलवार-सूट बिकने शुरू हो चुके हैं.

इसके हर धागे में कारीगरों की मेहनत और लखनऊ की तहजीब की झलक देखने को मिलती है. ऐसे में वेडिंग सीजन में अपनी वॉर्डरोब को

खास बनाने का यह सुनहरा मौका हो सकता है. आपको बता दें कि जून के महीने में शादियों के कई शुभ मुहूर्त हैं. ऐसे में अगर आपकी खुद की शादी है या किसी परिवार या दोस्त की शादी है तो आप चिकनकारी सलवार सूट, साड़ी या लहंगा खरीद कर दूसरों से अलग और बेहद खूबसूरत नजर आ सकती हैं.

दिल्ली के आईएनए दिल्ली हाट में लखनऊ की चिकनकारी लेकर के पहुंचे हैं. लखनऊ के ही कारोबारी मोहम्मद अरमान जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और पूरा कारखाना लखनऊ में ही है. पहली बार वह दिल्ली के आईएनए में अपना स्टॉल लेकर के आए हैं, जो अब हमेशा आईएनए दिल्ली हाट में लगेगा. 106 नंबर इनकी दुकान का नंबर है. लोकल 18 से खास बातचीत में मोहम्मद अरमान ने बताया कि लखनऊ की चिकनकारी पूरी दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि सिर्फ लखनऊ का चिकनकारी कपड़ा ही देश समेत दुबई, यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों में जाता है.

दिल्ली में चिकनकारी के यूं तो कई शोरूम और दुकानें हैं, लेकिन जो लखनऊ की असली चिकनकारी है. वो बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए दिल्ली के आईएनए दिल्ली हाट में लखनऊ की चिकनकारी को वह लेकर के आए हैं, जिसमें सलवार सूट, साड़ी और लहंगे मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि वह अभी सिर्फ महिलाओं का कलेक्शन लेकर आए हैं. आने वाले समय में पुरुषों के लिए भी कलेक्शन लेकर के आएंगे.

जानें इसकी क्या है कीमत

मोहम्मद अरमान ने बताया कि चिकनकारी कपड़े इसलिए महंगे होते हैं. क्योंकि इन्हें हाथों से बनाया जाता है. इसका एक-एक टांका हाथों से बनाया जाता है. एक साड़ी को बनने में 4 से 6 महीने का वक्त लगता है. जबकि कुर्तियां 2 से 3 दिन में तैयार होती हैं. सलवार सूट लगभग 1 से 2 महीने में तैयार होता है. इसीलिए चिकनकारी का कपड़ा गर्मियों में बहुत आरामदायक होता है और बेहद हल्का कपड़ा होता है. गर्मियों में चिकनकारी कपड़े की डिमांड देश के साथ-साथ विदेशों तक बढ़ जाती है. इसीलिए इसकी कीमत भी उसी हिसाब से रखी जाती है.

अगर आप कुर्ती खरीदेंगे तो वह आपको 200 से लेकर 400 रुपए में मिल जाएगी. वहीं, अगर आप सलवार सूट खरीदेंगे तो सलवार सूट में हर रेंज का कपड़ा मौजूद है यानी 1000 रुपए से लेकर 200000 रुपए तक के सलवार सूट है. इसके अलावा साड़ियों की बात करें तो साड़ियां भी 80000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक मौजूद हैं. यानी जैसा आपका बजट रहेगा, वैसी खरीदारी आप कर सकते हैं.

रातें रंगीन, पर शामें बेसुकून! लेट नाइट पार्टी और नशे के नए कल्चर से खो रही लखनऊ की तहजीब

पिछले दिनों विभूतिखंड थाना क्षेत्र में पार्टी के बाद मामूली विवाद में 28 वर्षीय शिवम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी

(जीएनएस)।

लखनऊः खास तहजीब, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए लखनऊ पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है. लखनऊ की आत्मा कहे जाने वाले पुराने लखनऊ की गलियों में आज भी वह अदब, सलीका और सुकून भरी शामें जिंदा हैं. वक्त के साथ लखनऊ का दायरा बढ़ा है, लेकिन इस बढ़ते दायरे में पुराना सौंदर्य कहीं खो सा गया है.

गोमती नगर, विभूतिखंड, गोमती नगर एक्सटेंशन और सुशांत गोल्फ सिटी जैसे इलाकों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, मॉल, बार सबकुछ है, जो दिखाता है कि शहर आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन इस आधुनिकता में लेट नाइट कल्चर भी बढ़ा है, जिससे आए दिन अपराध की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. चंद लोग भले ही इस चकाचौंध से खुश हों, जबकि हकीकत ये है कि लखनऊ की मूल सभ्यता यहां नदारद हो रही है और तेजी से अपराध बढ़ रहा है. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ लखनऊ से संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट

दरअसल, राजधानी लखनऊ पिछले एक दशक में आधुनिकता के

तौर पर काफी मजबूत हुआ है. नया बसा लखनऊ जो कि फैजाबाद रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड और शहीदपथ के आसपास है, वहां पर बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिस, मॉल और नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं. लखनऊ पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन हब के तौर पर भी उभर कर सामने आया है, यहां पर सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने भी अपना प्रभाव जमाया है. लिहाजा बड़ी संख्या में अन्य जिले व प्रदेश से लोग नौकरी करने और पढ़ने के लिए यहां पहुंचते हैं. ये लोग नए लखनऊ की तरफ रुख करते हैं क्योंकि वहां मेट्रो सिटीज की तरह मनोरंजन के लिए बड़ी संख्या में पब, बार लॉज खुल गए हैं. साथ ही युवा देर रात तक पार्टियां करते हैं.

पार्टियों में हो रहीं आपराधिक घटनाएं

राजधानी के लॉज, बार व पब में देर रात तक पॉर्टियां तो ठीक हैं, लेकिन इन पार्टियों में नशे की वजह से आपराधिक घटनाएं भी होती हैं. पिछले दिनों विभूतिखंड थाना क्षेत्र में ऐसे ही पार्टी के बाद एक मामूली विवाद में 28 वर्षीय शिवम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. ऐसे ही सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़े मॉल के बार में मामूली कहासुनी में एक युवक की पिटाई कर दी गई, जिसमें उसकी आंख में गंभीर चोटें आईं. इसी तरह विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित एक बार में आए दिन महिलाओं के आपस में मारपीट करते हुए वीडियो सामने आते हैं. यह सब लखनऊ के लिए नया है. इसलिए यहां के रहने वाले इसको लेकर असजह हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की वजह से नए क्षेत्र में बने बार व पब और रेस्टोरेंट में जाने से कतराते हैं.

लखनऊ में बदलते माहौल ने बढ़ाई चिंता - सुरक्षा के इंतजाम पर क्या बोले डीसीपी

बार और पब में लेट नाइट पार्टियां, वहां युवाओं से मारपीट जैसे मामलों पर डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद का कहना है कि इन क्षेत्रों में घटनाएं न हों, इसके लिए बड़े पैमाने पर यहां पेट्रोलिंग की जाती है. जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. किसी भी शिकायत पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिससे रात में भी लोग घूम फिर सकें. ऐसे में जो युवक यहां घूमने-टहलने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें मना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी तरह की कोई अपराधी घटना ना हो. यहां पर चलने वाले बार, पब व लॉच को संबंधित विभाग से लाइसेंस मिला हुआ. ऐसे में उन्हें बंद नहीं कराया जा सकता. उनके साथ मीटिंग कर हम समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करते हैं.

लखनऊ के इन इलाकों में बढ़ा है नाइट कल्चर - अपराध रोकने के लिए क्या है पुलिस का प्लान

विभूतिखंड, गोमतीनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बढ़ रहीं घटनाओं पर एडीसीपी डॉक्टर अमोल मुरकुटे ने कहा कि नाइट कल्चर की वजह से हुड़दंग होता है, जिसमें कई बार बड़ी आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए हमने यह प्लान तैयार किया है कि आबकारी विभाग के साथ पत्राचार करके यह निर्धारित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में स्थित बार और पब सिर्फ 12:00 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति दी जाए. साथ ही चौराहों पर जो सिगरेट व खाने-पीने की दुकानें सिर्फ 12:00 बजे तक ही खुलें.

लखनऊ में बेलगाम 'नाइट कल्चर' की खतरनाक टाइमलाइन - क्या कहते हैं लखनऊ डीएम

लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिस किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में बार को सिर्फ 12:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति के लिए संस्तुति करती है तो उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा. पहले भी पुलिस की संस्तुति के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बार लाइसेंस नहीं दिए गए. यदि किसी क्षेत्र में देर रात तक बार खुलने से अपराधी घटनाओं की संभावनाएं हैं तो उनका समय निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

यह हो सकती है चुनौती

लखनऊ जिला प्रशासन व पुलिस के लिए कुछ क्षेत्र की दुकानों को सीमित समय तक लाइसेंस देने के प्रयास को जमीन पर उतरना आसान नहीं होगा. आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दुकानों को लाइसेंस देने के समय का निर्धारण शासन स्तर से होता है. अगर समय में परिवर्तन करना है तो शासन को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा. शासन के निर्णय के बाद ही यह संभव होगा कि दुकानों का समय निर्धारित किया जाए. यह संभव नहीं है कि कुछ जगह पर आप 2:00 बजे तक लाइसेंस दें और कुछ जगह पर 12:00 तक का लाइसेंस दें. जब तक इसको लेकर शासन से गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक इसको जमीन पर उतरना थोड़ा कठिन होगा. अगर शासन से शासनादेश जारी नहीं होगा तो फिर लोग लाइसेंस की मांग को लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं.

सुरक्षा दावों पर क्या बोली लखनऊ पुलिस? - क्या कहते हैं जानकार

इस बारे में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल ने कहा कि लखनऊ का कल्चर यह नहीं है जो नए लखनऊ में डेवलप हो रहा है. जो नया लखनऊ बना है खासकर शहीद पथ के आसपास, वहां पर इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं. आलम यह है कि इस क्षेत्र में पुराने लखनऊ के लोग जाने से घबराते हैं. उन्हें डर रहता है कि अगर हम गए तो पता नहीं कब वहां वरदात हो जाए. इस तरह का जब कल्चर राजधानी लखनऊ में डेवलप हो रहा है तो जिला प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था पर लगाम लगाई जाए, जो लोगों के लिए असहज है और उससे आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

'नाकाम व्यवस्था है कारण'

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता वर्षा सिंह ने कहा कि नाइट आउट का जो कल्चर बना है, यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है. यह एक तरीके से व्यवस्था का फेलियर है, जिस तरह से क्लब और बार के देर रात तक खुले रहने से मारपीट, हत्या, महिलाओं की आपस में मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती हैं, इससे साबित होता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को बनाने में नाकामयाब नजर आ रहा है. अगर इनके संचालन के साथ-साथ व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो सभी विभागों को व्यापक व्यवस्थाएं करनी होगी. पुलिस को अतिरिक्त पेट्रोलिंग करनी होगी. इसी के साथ-साथ बार संचालक पर जवाबदेही भी तय करनी होगी.

बढ़ते अपराध पर क्या बोले लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर? - बेलगाम हैं बार और पब

नए लखनऊ में स्थित कई बार और पब बेलगाम नजर आते हैं. यहां पहुंचने वाले लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. कई जगह तो युवाओं से एंट्री फीस ली जाती है, जबकि अंदर महिलाएं मौजूद होती हैं, जिनकी एंट्री फ्री होती है. फिर वो पब संचालकों के इशारे पर युवकों से दोस्ती करती हैं और उनका बिल बढ़ाती हैं. ज्यादा बिल बनने पर जब युवक विरोध करता है तो पब के कर्मचारी उससे वसूली के नाम पर मारपीट करते हैं. इसको लेकर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बीते दिनों एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी.

इस वजह से पुलिस नहीं लगा पा रही लगाम

पुलिस के सामने चुनौती यह है कि आबकारी विभाग से इन्हें लेट नाइट तक शराब परोसने का लाइसेंस मिल जाता है. आबकारी नीति के तहत वैसे तो शराब दुकान खुले रहने का समय रात 10:00 बजे तक है, लेकिन अतिरिक्त पैसा देकर और विशेष आयोजन के नाम पर कई बार और पब मलिक रात के 2:00 बजे तक का लाइसेंस ले लेते हैं. लाइसेंस लेने के बाद इनकी मनमानी शुरू हो जाती है.

व्यवस्था के फेलियर पर क्या कहते हैं जानकार

पुलिस अधिकारी अगर जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो लाइसेंस दिखाकर बार संचालक वैध होने की बात करते हैं. ऐसे में जब तक कोई घटना या दुर्घटना नहीं होती, तब तक पुलिस इन बार व पब मालिक व हुड़दंग करने वाले युवा-युवतियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती. पुलिस के सामने यह भी चुनौती होती है कि अगर रात में सड़कों पर गाड़ियों से घूम रहे युवकों को टोका जाता है तो वह अपनी आजादी की बात कह कर पुलिस से बहस शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर प्रभावशाली परिवारों के लोग पहुंचते हैं. ऐसे में पुलिस की ज्यादा रोक-टोक करने पर उन्हें ही कानून का पाठ पढ़ा दिया जाता है.

पीएम मोदी का दिया हीरा अपने पास रखना चाहती थीं जिल बाइडन, लेकिन इस वजह से अमेरिकी सरकार को लौटाना पड़ा

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2023 की अमेरिका यात्रा के दौरान जिल बाइडन को भेंट किया गया 7.5 कैरेट का लैब-ग्रोन हीरा उनकी सबसे यादगार सौगातों में शामिल रहा। अपनी आत्मकथा में बाइडन ने लिखा कि वह हीरा अपने पास रखना चाहती थीं, लेकिन अमेरिकी नियमों के तहत संघीय सरकार को लौटाना पड़ा। उन्होंने इसे कार्यकाल के दौरान आधिकारिक आयोजनों में पहना, लेकिन पद छोड़ने के बाद वापस कर दिया।

अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला डॉ. जिल बाइडन ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपहार में दिए गए हीरे को अपने पास रखना चाहती थीं, लेकिन उसकी अधिक कीमत के कारण उन्होंने उसे संघीय सरकार को लौटा दिया। अपनी आत्मकथा 'व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंगः ए मेमोइर' में बाइडन ने व्हाइट हाउस के जीवन और अमेरिका के प्रथम परिवार को मिलने वाले उपहारों से जुड़े सख्त नियमों का विस्तार से वर्णन किया है। यह पुस्तक इसी सप्ताह बाजार में आई है।

पीएम मोदी ने भेंट किया था 7.5 कैरेट का लैब-ग्रोन डायमंड

बाइडन को सबसे अधिक याद रहने वाले उपहारों में एक 7.5 कैरेट का लैब-ग्रोन डायमंड भी शामिल है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी वॉशिंगटन स्थित राजकीय यात्रा के दौरान भेंट किया था। बाइडन लिखती हैं, 'कभी-कभी उपहार के रूप में छोटी-छोटी चीजें मिलती थीं, जैसे फूल या शराब, लेकिन कभी-कभी बड़ी चीजें भी मिलती थीं। इनमें 7.5 कैरेट का वह लैब-ग्रोन डायमंड भी शामिल था, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजकीय यात्रा के दौरान मुझे दिया था। यह रत्न प्रयोगशाला में निर्मित हीरों के क्षेत्र में अग्रणी बनने के भारत के प्रयासों का प्रतीक था'।

हीरे को लेकर क्या थी जिल बाइडन की योजना

बाइडन आगे लिखती हैं, 'यह हीरा बेहद खूबसूरत था। अमेरिकी नैतिक नियमों के अनुसार यह उपहार व्यक्तिगत रूप से मेरा नहीं था। तकनीकी रूप से यह मुझे नहीं, बल्कि प्रथम महिला के पद को दिया गया था, इसलिए यह संघीय सरकार की संपत्ति माना गया'। उन्होंने बताया कि एक निश्चित मूल्य से अधिक के उपहारों की

सरकारी अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाती है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे उपहारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उनके उचित बाजार मूल्य का भुगतान कर उन्हें खरीद सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के उपहार के मामले में उन्होंने शुरूआत में ऐसा करने पर विचार किया था।

पहले खरीदने का मन बनाया फिर कीमत जानकर टाल दिया विचार

बाइडन लिखती हैं, 'प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह उनके गृहनगर में 2,500 डॉलर में हस्तनिर्मित किया गया था। उनके पास इसकी रसीद भी थी। मैंने सोचा था कि शायद मैं इसे खरीद लूं। लेकिन बाद में विदेश विभाग ने इसकी कीमत 20,000 डॉलर आंकी, इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा'। उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे बताया गया कि मैं इसे अपने कार्यालय में प्रदर्शित कर सकती हूं या पहनने के लिए उधार ले सकती हूं। इसलिए मैंने इसे अंगूठी में जड़वा लिया और आधिकारिक समारोहों में पहनती थी। यह व्यवस्था केवल व्हाइट हाउस में मेरे कार्यकाल तक ही रही। पद छोड़ने के बाद मैंने इसे वापस कर दिया। अंगूठी को अन्य अनगिनत राष्ट्रपति उपहारों के साथ एक गोदाम में रख दिया गया, जिनमें से कई को बाद में नष्ट कर दिया गया'।

यह संस्मरण इस घटना के माध्यम से व्हाइट हाउस के जीवन से जुड़े उन वित्तीय और नैतिक नियमों को रेखांकित करता है, जिन्हें अक्सर लोग ठीक से नहीं समझ पाते। बाइडन लिखती हैं कि आधिकारिक आवास, कार्यक्रमों और उपहारों से जुड़े विस्तृत नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग सरकारी संसाधनों या विदेशी उपहारों से व्यक्तिगत लाभ न उठा सकें।

जिल बाइडन ने कई अन्य उपहारों का भी किया जिक्र

बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए हीरे की तुलना फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों द्वारा दिए गए एक कंगन से की है। इस कंगन का उनके लिए भावनात्मक महत्व था, इसलिए उन्होंने सरकार से इसे खरीद लिया ताकि पद छोड़ने के बाद भी वह इसे अपने पास रख सकें। बाइडन लिखती हैं, 'मैंने विदेश विभाग को भुगतान किया ताकि पद छोड़ने के बाद भी मैं इसे अपने पास रख सकूं। मैं इसे आज भी हर दिन पहनती हूं'। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले अन्य उपहारों का भी उल्लेख किया है। इनमें 'यूक्रेन द्वारा बम के छर्रों से बनाया गया एक ब्रोच' भी शामिल है, जिसकी कीमत अधिकारियों ने 14,063 डॉलर आंकी थी।

जून 2023 में पीएम मोदी ने की थी अमेरिका की यात्रा

2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा बाइडन प्रशासन के दौरान नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक मुलाकातों में से एक थी। व्हाइट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक भारतीय-अमेरिकी शामिल हुए थे। इस यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का आयोजन किया गया था और रक्षा, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर तथा रणनीतिक क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग को प्रमुखता से रेखांकित किया गया था।

मानव सुथार का परिवार स्टेडियम छोड़ क्यों चला गया? बेटे की सफलता नहीं देखने का बड़ा कारण

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लानपुर टेस्ट मैच में अपना शानदार डेब्यू किया है। इस खास मौके पर उनके माता-पिता और बहन उन्हें टेस्ट कैप मिलते देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे थे। हालांकि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनका परिवार अचानक वापस अपने घर लौट गया।

खिलाड़ी के पिता जगदीश सुथार ने बताया कि उनका परिवार मुकाबले को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस था। इसी घबराहट और एक खास अंधविश्वास के चलते उन्होंने स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच न देखने का फैसला किया। उन्हें लगा कि टीवी के सामने बैठकर दुआ करना उनके बेटे के खेल के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।

मैदान पर दिखा शानदार प्रदर्शन

परिवार का यह अंधविश्वास आखिरकार टीम इंडिया और मानव के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। इस युवा स्पिनर ने मैच के दूसरे दिन अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से

अफगानिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। उन्होंने केवल 21 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

बचपन के कोच को दिया श्रेय

राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले जगदीश सुथार खुद एक रिटायर्ड पीटीआई हैं। उन्होंने अपने बेटे की इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय मानव की कड़ी मेहनत और उनके बचपन के कोच धीरज शर्मा को दिया है। उनका मानना है कि सही मार्गदर्शन की वजह से ही उनका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है।

पिता का हमेशा मिला पूरा साथ

जब मानव महज 11 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट एकेडमी में दाखिला कराया था। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा खुलकर खेलने की आजादी दी और हर परिस्थिति में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। पिता के इसी भरोसे ने मानव को बिना किसी दबाव के आगे बढ़ने की हिम्मत दी।

घर में बेहद शांत रहते हैं मानव

मैदान पर अपनी फिरकी से कमाल करने वाले मानव अपने घर पर बेहद शांत स्वभाव के रहते हैं। वह परिवार के साथ घरेलू माहौल में क्रिकेट को लेकर ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें कि यह युवा खिलाड़ी भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अपना आदर्श मानता है।

मकान मालिकों ने छात्रा और महिला से की अश्लीलता

(जीएनएस)।

लखनऊ। हसनगंज की छात्रा और बीबीडी इलाके की महिला ने मकान मालिकों पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने संबंधित थानों में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। हसनगंज निवासी छात्रा ने मकान मालिक अंबुज त्रिवेदी पर आरोप लगाया। छात्रा के मुताबिक, पांच जून को अंबुज ने पत्नी की अनुपस्थिति में उसे फोन कर अश्लीलता की। उसने कमरे में आने का दबाव डाला व छेड़छाड़ भी की। इंस्पेक्टर चितवन कुमार के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।

वहीं, बीबीडी की महिला ने मकान मालिक प्रमोद कुमार वर्मा पर आरोप लगाया। महिला के अनुसार, प्रमोद उस पर शादी का दबाव डालता व छेड़छाड़ करता था। इससे उन्हें उसका घर छोड़ना पड़ा। चार जून को प्रमोद ने उनके पति को पीटा। बीच-बचाव करने पर उसने उनसे भी अश्लीलता की। इंस्पेक्टर राम सिंह के अनुसार, आरोपी की तलाश की जा रही है।

लखनऊ में बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला:सिलेंडर से सिर फोड़ा, टांग पकड़कर सड़क पर फेंका; बोला- जिसे जो करना हो कर लो

(जीएनएस)।

लखनऊ में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। मां-बाप से मारपीट का विरोध करने पर घरेलू गैस सिलेंडर से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। खून से लथपथ छोटे भाई को टांग पकड़कर घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया।

चिल्लाते हुए बोला- इसे मार डाला, जिसे जो करना हो कर ले। मौके पर पहुंचे चाचा और आसपास के लोग छोटे भाई को ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-3 में हुई। मृतक आर्यन मिश्र (21) बीज भंडार में काम करता था। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई अभिषेक मिश्रा (24) को हिरासत में ले लिया है।

आर्यन के पिता रामानंद मिश्रा पेंटिंग का ठेका लेकर काम कराते हैं। उन्होंने बताया- छोटा बेटा आर्यन डालीगंज स्थित बीज भंडार में दवा सप्लाई का काम करता था। बड़ा बेटा अभिषेक कुछ नहीं करता है।

अभिषेक नशा करने के बाद अक्सर सबसे मारपीट करता था। रविवार सुबह उसने पहले मुझसे मारपीट की। हम किसी तरह उससे बचकर छत पर भाग गए। इसके बाद

तैयार होकर दुकान का सामान लेने के लिए पत्नी के साथ यहियागंज जाने लगे।

इस दौरान अभिषेक ने अपनी मां मंजू मिश्रा की पिटाई शुरू कर दी। सड़क पर ही उनको लात मारने लगा। मोहल्लेवालों ने बीच-बचाव कराया। छोटे बेटे आर्यन ने इसका विरोध किया, तो अभिषेक ने उसके साथ गाली-गलौज की। उसके बाद उसके सिर पर सिलेंडर से वार कर दिए।

पिता रामानंद मिश्रा ने बताया- बड़ा बेटा नशे का आदी है। कोई काम-धंधा नहीं करता है।

पिता रामानंद मिश्रा ने बताया- बड़ा बेटा नशे का आदी है। कोई काम-धंधा नहीं करता है।

दोनों भाइयों का पहले सड़क पर झगड़ा हुआ

पड़ोस में रहने वाले शिवपूजन मिश्र ने बताया- सुबह के समय झगड़े के बाद रामानंद अपनी पत्नी के साथ चले गए। इसके बाद भी दोनों भाइयों के बीच झगड़ा चलता रहा। सड़क पर काफी मारपीट हुई, तो पड़ोस में रहने वाले किराएदार और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को हटा दिया।

अभिषेक को घर के अंदर भेज दिया, जबकि आर्यन को घर से सटे दूसरे मकान के अंदर कर दिया। इस दौरान छत के रास्ते आर्यन फिर अभिषेक के पास चला गया, जहां दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ।

पड़ोसी ने बताया कि बड़ा भाई छोटे भाई को घसीटता हुआ घर से बाहर लाया। । पड़ोसी ने बताया कि बड़ा भाई छोटे भाई को घसीटता हुआ घर से बाहर लाया। ।

'अभिषेक के सिर पर खून सवार था'

अभिषेक ने उसके सिर पर सिलेंडर से वार कर दिए, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इससे भी अभिषेक का मन नहीं भरा तो उसकी टांग पकड़ कर खींचते हुए सड़क पर ले आया। फिर मोहल्लेवालों से कहने लगा इसको मार दिया। अब जिसको जो करना है कर लो। इस पर आर्यन को गंभीर हालत में चाचा परमानंद ने मोहल्लेवालों की मदद से ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सचिव ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा सेतु परियोजना कार्य का लिया जायजा, जुलाई के पहले सप्ताह तक हो जाएगा पूर्ण

19.76 किमी लंबा, जिसमें 9.76 किमी का पुल और 10 किमी का अप्रोच रोड शामिल है, कच्ची दरगाह बिदुपुर 6-लेन गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। जुलाई 2026 के पहले सप्ताह तक पूरा होने का लक्ष्य पटना-उत्तरी बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, यात्रा के समय को कम करेगा और गांधी सेतु पर यातायात को आसान करेगा।

(जीएनएस)।

पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाल ने आज कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सचिव को बताया कि इस परियोजना को तेजी से पूरा किया जा रहा है और परियोजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। *बचे हुये कार्य को जुलाई के पहले सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जायेगा।* बिहार के परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जो राजधानी पटना और उत्तर बिहार के बीच कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देगी।

विभाग के सचिव ने कार्य की गुणवत्ता की सराहना करते हुए निर्माण एजेंसी और परियोजना से जुड़े अभियंताओं को निर्देश दिए कि अंतिम

चरण के कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए। *उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी तकनीकी मानकों का पालन करते हुए कार्य को जुलाई, 2026 के पहले सप्ताह तक हर हाल में पूरा कर लिया जाय, ताकि आम जनता के लिए इस मार्ग को शीघ्र खोला जा सके।*

पटना जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सख्या-103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 किमी लम्बाई के 6 लेन ग्रीनफिल्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 9.76 किमी लम्बा पुल तथा 10 किमी लम्बा पहुंच पथों का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना का भौतिक कार्य (ढँ८ऱ्रू' ढ१ङ्क्ष्१२२) 98.1 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। वर्तमान में पुल पर फिनिशिंग कार्यों के साथ-साथ एक्सपेंशन जॉइंट्स की स्ट्रेसिंग और अन्य तकनीकी कार्य चल रहे हैं। प्रथम चरण में कच्ची दरगाह, पटना से राघोपुर दियारा, वैशाली (कुल लम्बाई 4.57 किमी) का उद्घाटन किया जा चुका है।

यह सिक्स-लेन पुल, जो कि पटना के सबलपुर को एनएच-103 (बिदुपुर) से जोड़ता है, पटना-बख्तियारपुर बाईपास (एनएच-30) से सीधे जुड़ा होगा। सचिव ने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क सम्पर्कता मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिये पटना पहुँचने में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी।

यह परियोजना न केवल गंगा नदी को पार करने का एक सुगम मार्ग प्रदान करेगा, बल्कि हाजीपुर और समस्तीपुर की ओर जाने वाले यातायात को भी सुगम बनाएगा। यह मेगा प्रोजेक्ट पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।सिक्स लेन पुल बिदुपुर तक शुरू किए जाने के बाद गांधी सेतु पर दबाव कम होगा।

जल संरक्षण पर मध्यप्रदेश मॉडल को मिली अंतरराष्ट्रीय सराहना, विदेशी राजनयिकों ने बताया अनुकरणीय

मध्य प्रदेश के जल गंगा संवर्धन अभियान ने सरकारी योजना से एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। सदानीरा संगम में छह देशों के राजनयिकों ने नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए इस पहल की सराहना की, और दुनिया भर में इसी तरह के मॉडल को प्रेरित करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।

(जीएनएस)।

जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की पहल को अब वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के जरिए प्रदेश ने जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देते हुए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। भोपाल स्थित भारत भवन में आयोजित 'सदानीरा समागम' में छह देशों के राजनयिकों ने इस मॉडल की खुलकर प्रशंसा की और इसे अपने-अपने देशों में लागू करने की इच्छा जताई।

कार्यक्रम में साइप्रस, फिजी,

मेक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और इक्वाडोर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि जल संकट आज वैश्विक चुनौती बन चुका है और मध्यप्रदेश का यह प्रयास समाधान की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' अब केवल सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि व्यापक जनभागीदारी के साथ एक जन-आंदोलन बन चुका है। नदियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

साइप्रस और फिजी ने की सराहना

साइप्रस के उच्चायुक्त इवागोरस वराईओनाइडेस ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए जन-जागरूकता बेहद जरूरी है और मध्यप्रदेश का मॉडल इस दिशा में प्रेरणादायक है। वहीं, फिजी के उच्चायुक्त जगन्नाथ सामी ने जलवायु परिवर्तन को गंभीर चिंता बताते हुए इस पहल को दूरदर्शी बताया।

मेक्सिको और नेपाल ने बताया साझा जिम्मेदारी

मेक्सिको की प्रतिनिधि वनेसा एड्रियन ने जल संरक्षण को वैश्विक जिम्मेदारी बताते हुए इसे सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की सराहना की। नेपाल के प्रतिनिधि दीपक पोरखिरे ने कहा कि यह आयोजन प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है और भारत-नेपाल की सांस्कृतिक समानताओं को भी उजागर करता है।

त्रिनिदाद-टोबैगो और इक्वाडोर अपनाएंगे मॉडल

त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रतिनिधि चंद्रदत्त सिंह ने इस पहल को जन-जन तक पर्यावरणीय संदेश पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया। वहीं, इक्वाडोर के प्रतिनिधि जॉर्ज विनिशियो अनरंगो ने घोषणा की कि वे अपने देश में भी इसी तरह का आयोजन करेंगे।

लखनऊ की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है सिस्टम और पब्लिक की 50-50 पार्टनरशिप!

लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प तब तक अधूरा है, जब तक नगर निगम की सुस्ती और आम जनता की लापरवाही दूर नहीं हो जाती। लखनवाइट्स का मानना है कि शहर को चमकाने के लिए अब केवल कागजी दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सिस्टम को जवाबदेह और जनता को जिम्मेदार बनना होगा।

(जीएनएस)।

लखनऊ , लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प तब तक अधूरा है, जब तक नगर निगम की सुस्ती और आम जनता की लापरवाही दूर नहीं हो जाती। लखनवाइट्स का मानना है कि शहर को चमकाने के लिए अब केवल कागजी दावों से

काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सिस्टम को जवाबदेह और जनता को जिम्मेदार बनना होगा। 'दैनिक जागरण आईनेक्स्ट' की 'क्लीन सिटी चैलेंज' पहल से जुड़े लोगों ने कहा कि नियमित सफाई, 100 परसेंट डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन और बंद नालियां ही शहर की सूरत बदल सकती हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति की सख्त जरूरत है। जब तक नगर निगम एक्टिव नहीं होगा, लोग सड़कों को डस्टबिन समझना बंद नहीं करेंगे

हर सप्ताह हो समीक्षा

लोगों ने यह भी सुझाव दिए हैं कि निगम के सफाई कर्मियों की मॉनीटरिंग के लिए भी कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाए, जिससे निगम कर्मी समय से फील्ड में पहुंचे और सफाई करें। ज्यादातर लोगों ने यह भी सुझाव दिए हैं कि हर सप्ताह वार्ड या जोन के हिसाब से सफाई व्यवस्था की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि गलियों से कब से वेस्ट नहीं उठा है और अगर उठा है तो क्या उसका उचित निस्तारण किया गया है। समीक्षा से यह पता चलेगा कि गली मोहल्लों में सफाई व्यवस्था के पटरी पर न आने के प्रमुख कारण क्या हैं, जिन्हें दूर करने के कदम उठाए जा सकते हैं।

यूपी की महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए योगी ने बनाया मेगा प्लान, युवाओं को भी मिलेगा फायदा

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई स्टार्टअप नीति-2026 और नई डाटा सेंटर नीति के मसौदे की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ऐसी नीतियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जो युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाएं।

उन्होंने वर्ष 2030 तक प्रदेश में दो गीगावाट से अधिक अतिरिक्त डाटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य भी तय किया। साथ ही स्टार्टअप गतिविधियों के संचालन, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन गठित करने की भी आवश्यकता बताई।

रविवार को आईटी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नई स्टार्टअप नीति के प्रविधानों में भरण-पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता, पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

साथ ही महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों व पूर्वांचल और बुंदेलखंड के स्टार्टअप्स को विशेष

सहायता देने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018 में स्टार्टअप रैंकिंग में 'एस्पायरिंग लीडर' श्रेणी में रहने वाला उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष 'टॉप परफार्मर' श्रेणी में आ चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को निवेशकों, उद्योग जगत, अनुसंधान संस्थानों और एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें पूंजी, तकनीकी सहयोग, मेंटरशिप और नए बाजारों तक पहुंच मिल सके।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, क्वांटम तकनीक, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलाजी और हेल्थ-टेक जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए।

इसके लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने और विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों व उद्योग जगत के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने पर बल दिया गया। लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित यू-हब को डीप-टेक नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

लखनऊ समेत अन्य शहरों में भी बनेगा डाटा सेंटर क्लस्टर

डाटा सेंटर क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई डेटा सेंटर नीति को पहले से अधिक आकर्षक, प्रतिस्पर्धी और निवेशक अनुकूल बनाया जाए।

डाटा सेंटर विकास केवल एनसीआर तक सीमित न रहे, बल्कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, सीतापुर और अन्य शहरों में भी डाटा सेंटर क्लस्टर विकसित किए जाएं। उन्होंने एआई आधारित उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधाओं और ग्रीन डाटा सेंटर को विशेष प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए।

आईटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 21,342.90 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं और 644 मेगावाट क्षमता पर काम चल रहा है। वर्तमान में छह डाटा सेंटर पार्क और दो डाटा सेंटर इकाइयां संचालित हैं।

विभिन्न निवेशकों ने प्रदेश में 5,410 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर विकसित करने में रुचि दिखाई है, जिनमें करीब 4.90 लाख करोड़ रुपये निवेश की संभावना है।

ट्रस्ट की ऑडिट के बीच अखिलेश यादव ने राम मंदिर के दान से लापता धनराशि पर चिंता जताई, अदालत से इस मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के लिए दिए गए दान की बड़ी रकम गायब होने की रिपोर्टों पर चिंता जताई है। उन्होंने अदालत से इस मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। इसके जवाब में, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, चंपत राय ने कहा कि चल रहे आंतरिक ऑडिट में इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।

(जीएनएस)।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ नियमित ऑडिट करता है। राय के अनुसार, वर्तमान ऑडिट प्रक्रिया में कोई अनियमितता सामने नहीं आई है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेंद्र दास ने भगवान राम के न्याय में विश्वास व्यक्त किया और कहा कि सरकार के किसी भी फैसले का सम्मान किया जाएगा।

यादव ने इस मुद्दे को दुनिया भर के राम भक्तों के लिए अत्यधिक संवेदनशील बताया और मंदिर ट्रस्ट की चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने ट्रस्ट और सरकार दोनों की प्रतिक्रिया की कमी पर सवाल उठाते हुए इसे संदिग्ध बताया। यादव ने वैश्विक सनातनी समुदाय द्वारा भगवान राम में रखे गए गहरे विश्वास के कारण अदालत के हस्तक्षेप का आग्रह किया।

एक्स पर एक पोस्ट में, यादव ने राय के बयान को अस्पष्ट और नियमित बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी ट्रस्ट सदस्यों को एक व्यापक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बैठक करनी चाहिए और सत्यापन के लिए सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करने की सलाह दी। यादव ने तर्क दिया कि ट्रस्टियों के बीच सामूहिक चर्चा से सच्चाई सामने आएगी।

ट्रस्ट की प्रतिक्रिया और ऑडिट प्रक्रिया

राय ने कहा कि अब तक के ऑडिट में कुछ भी उल्लेखनीय सामने नहीं आया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये ऑडिट मानक प्रक्रियाएं हैं जिनमें कई हितधारक शामिल हैं। इसके बावजूद, यादव संशयवादी बने रहे, और उन्होंने सवाल उठाया कि एक संक्षिप्त बयान जारी करने में इतना समय क्यों लगा और इसकी सामग्री की कमी की आलोचना की।

सपा नेता ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जिसे उन्होंने अपर्याप्त स्पष्टीकरण बताया, उसके बाद वैश्विक सनातन समुदाय की आशंकाएं बनी हुई हैं। उन्होंने इन गंभीर आरोपों को दूर करने के लिए सभी संबंधित पक्षों से पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

चिकित्सा लापरवाही के आरोपों के बीच चौरी चौरा अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई

(जीएनएस)।

रविवार को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अपने पहले बच्चे को जन्म देने के कुछ ही देर बाद 28 वर्षीय नीलम निषाद की मौत हो गई। उनके परिवार ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि सीएचसी अधीक्षक सर्वजीत प्रसाद ने चिकित्सा देखभाल में किसी भी कमी से इनकार करते हुए उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया है।

देवरिया जिले के बेलवाऊ्रुङ्ग८' गांव की रहने वाली नीलम को प्रसव पीड़ा के कारण शनिवार को सीएचसी में भर्ती कराया गया था। एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के बाद, उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। उनके पति देव निषाद और भाई रितेश ने दावा किया कि सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और आरोप लगाया कि रात के दौरान अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई।

घटना के जवाब में, नीलम के परिवार ने उनके शव को सीएचसी के बाहर रख दिया और सुबह लगभग 5:00 बजे चिकित्सा कर्मचारियों से जवाबदेही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन लगभग छह घंटे तक चला जब तक कि सर्किल ऑफिसर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। चौरी चौरा के विधायक सर्वण निषाद ने भी अस्पताल का दौरा किया और सीएचसी अधीक्षक से मुलाकात की।

अधिकारियों द्वारा परिवार को गहन जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया। इसके बाद, मौत के कारण का पता लगाने के लिए नीलम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस घटना पर राजनीतिक हस्तियों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नीलम की मौत के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यादव ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भी आलोचना की कि वे विभागीय जिम्मेदारियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।

यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चल रही चिंताओं को उजागर करती है और चिकित्सा लापरवाही के आरोपों की शीघ्र जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इन चिंताओं को दूर करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में पोस्टमार्टम परीक्षा और बाद की पूछताछ का परिणाम महत्वपूर्ण होगा।